

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1121
उत्तर देने की तारीख 08 फरवरी, 2023

4जी नेटवर्क

1121. श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के कई जिले/गांव 4जी नेटवर्क से वंचित हैं;
(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इन जिलों और गांवों को 4जी सेवाएं कब तक प्रदान की जाएंगी?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ख) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों और राज्य सरकारों द्वारा मार्च 2022 तक उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार देश के 6,44,131 गांवों में से (गांवों की संख्या भारत के महापंजीयक के नवंबर 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार हैं) में से लगभग 5,98,951 (93%) गांवों में 4जी मोबाइल नेटवर्क है तथा 45,180 गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य के 1,05,531 गांवों में से लगभग 1,05,146 (99.6%) गांवों को 4जी मोबाइल नेटवर्क के साथ कवर किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध-1 में संलग्न हैं।

(ग) सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) देश में चरणबद्ध तरीके से दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध कराते हैं। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से वित्त पोषण के माध्यम से सरकार देश के गांवों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। 4जी मोबाइल कवरेज के लिए प्रमुख यूएसओएफ स्कीमें इस प्रकार हैं:

- देश भर के सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं का संचयन। अनुमानित परियोजना लागत 26,316 करोड़ रुपये है।
- वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्र चरण-II में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान। अनुमानित परियोजना लागत 2,211 करोड़ रुपये है।
- वामपंथी उग्रवाद के चरण-I की सभी साइटों का 2जी से 4जी मोबाइल प्रौद्योगिकी में उन्नयन। अनुमानित परियोजना लागत 2,425 करोड़ रुपये है।
- एनईआर के लिए व्यापक दूरसंचार विकास कार्यक्रम के तहत देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान। अनुमानित परियोजना लागत 3,637 करोड़ रुपये है।
- 7,287 आकांक्षी जिला (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा) के गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान और चार राज्यों (अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान) के आकांक्षी जिलों के 502 सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान। परियोजनाओं की अनुमानित लागत 7,152 करोड़ रुपये है।
- जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, सीमा क्षेत्र और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के सेवा से वंचित 354 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान। परियोजनाओं की अनुमानित लागत 337 करोड़ रुपये है।
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सेवा से वंचित 85 गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज और एनएच 223 पर निर्बाध 4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान करना। इस परियोजना की अनुमानित लागत 130 करोड़ रुपए है।

अनुबंध-1

माननीय संसद सदस्यों द्वारा लोकसभा में दिनांक 08/02/2023 को "4जी नेटवर्क" के संबंध में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1121 के भाग (क) से (ख) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध।

देश के गांवों में 4जी कवरेज की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति निम्नानुसार (मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार) है

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरजीआई आंकड़ों के अनुसार गांवों की कुल संख्या (दिनांक 30-11-2019 तक)	4जी मोबाइल के साथ कवर किए गए गांवों की संख्या	4जी सेवा रहित गांवों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	559	105	454
2	आंध्र प्रदेश	17328	14159	3169
3	अरुणाचल प्रदेश	5993	2262	3731
4	असम	26429	24223	2206
5	बिहार	44888	44575	313
6	छत्तीसगढ़	20072	17482	2590
7	चंडीगढ़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	95	62	33
9	गोवा	392	342	50
10	गुजरात	18425	17604	821
11	हरियाणा	6640	6629	11
12	हिमाचल प्रदेश	20852	18970	1882
13	जम्मू और कश्मीर	6474	5643	831
14	झारखंड	32370	30050	2320
15	कर्नाटक	29818	28634	1184
16	केरल	1438	1358	80
17	लद्दाख	243	92	151
18	लक्षद्वीप	27	10	17
19	मध्य प्रदेश	55058	51818	3240
20	महाराष्ट्र	43931	40138	3793

21	मणिपुर	2612	2069	543
22	मेघालय	7100	4580	2520
23	मिजोरम	867	618	249
24	नागालैंड	1535	1073	462
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	55	55	0
26	ओडिशा	51176	43584	7592
27	पुदुचेरी	96	95	1
28	पंजाब	12534	12519	15
29	राजस्थान	46077	42343	3734
30	सिक्किम	461	157	304
31	तमिलनाडु	16488	15916	572
32	तेलंगाना	10203	9951	252
33	त्रिपुरा	937	638	299
34	उत्तर प्रदेश	105531	105146	385
35	उत्तराखंड	16456	15215	1241
36	पश्चिम बंगाल	40971	40836	135
	कुल	644131	598951	45180
